S. Son

प्रेषक.

डा० मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया—रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग—1 देहरादूनः दिनांक— 13 नवम्बर, 2017 विषयः— प्लास्टिक केट्स की दर अनुमोदित एवं कय की स्वीकृति विषयक। महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0—350/उद्यान/2017—18, दिनांकः 09 अक्टूबर, 2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि विभागीय निविदा समिति एवं आपके द्वारा की गयी संस्तुति के कम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017—18 में प्लास्टिक केट्स हेतु आमंत्रित विभागीय ई—निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर प्लास्टिक केट्स की मात्रा (संख्या में) 10860 नगं रू० 244 प्रति नग (समस्त करों सहित) की दर से मैं0 एम0एम0 सैल्स, पसरटा बाजार, बाराद्वारी, हाथरस, उ०प्र० के कय हेतु अनुमानित व्यय रू० 26.49840 (रू० छब्बीस लाख उनपचास हजार आठ सौ चालीस मात्र) अथवा योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत, जो भी कम हो, के व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:—

- (I) उक्त स्वीकृति केवल चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु प्रदान की जा रही है। उक्त दर एवं सामग्री की अधिप्राप्ति/कय की कार्यवाही अवधि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांकः 31 मार्च, 2018 तक ही प्रभावी/अनुमन्य होगी। उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वास्तविक मॉग एवं सगत मदों में उपलब्ध बजट सीमा के अन्तर्गत होगी। उक्त सामग्री की अधिप्राप्ति अनुमोदित निविदा शर्तो के अनुसार एवं नियमानुसार की जाएगी। यदि व्यय की मानक मदें स्वीकृत नयी योजनाओं के अन्तर्गत आती हो तो सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना के मानक सक्षम स्तर से अनुमोदित हो। बिना मानकों के अनुमोदन से पूर्व योजना के कियान्वयन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन योजना/योजनाओं के मानक मदों के अन्तर्गत उक्त सामग्री के कय का व्यय प्रस्तावित है, उस योजना/योजनाओं के संचालन की निर्धारित/अनुमोदित योजना अवधि गतिमान है।
- (II) गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सैम्पलिंग एवं पूरे स्टॉक की जॉच की जायेगी।

कमशः—<u>2</u> २ । १२२४ -

- (III) सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्टॉक का सत्पादन किया जायेगा।
- (IV) समस्त क्यादेश निविदाकर्ता अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे, उसके द्वारा अधिकार प्रतिनिधानित नहीं किया जायेगा।
- (V) निविदाकर्ता अधिकारी द्वारा स्वंय सुनिश्चित किया जायेगा, कि क्यादेश के अनुसार समस्त सामग्री नियत समय पर गन्तव्य स्थान पर पहुँचे एवं वितरित हों।
- 2. उक्त हेतु व्यय शासनादेश संख्याः 129/XXVII(7)/32/2017, दिनांकः 14 जुलाई, 2017, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 400/XXVII(7)/32/2015, दिनांकः 01 अप्रैल, 2015 भण्डार क्या प्रक्रिया (स्टोर पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम संग्रह खण्ड—5 भाग—1 सम्बन्धी नियम, शासनादेशों एवं अन्य समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

भवदीय, (डा० मेहरबान सिंह बिष्ट) अपर सचिव।

## संख्या-1791(1)/XVI(1)/17/5(35)/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3. समस्त मुख्य / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4. व्यय वित्त नियंत्रण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 5. ्रिनदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा० मेहरबान सिंह बिस्ट्र) रे अपर सचिव 🗥